# महाराष्ट्र में शुरू नहीं होगी गन्ने की पेराई

जयश्री भोसले | पुणे

दक्षिणी महाराष्ट्र की शुगर मिलों ने गन्ने की पेराई शुरू नहीं करने का फैसला लिया है क्योंकि किसान संगठनों ने गन्ने के फेयर एंड रेमुनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) से 200 रुपये ज्यादा की मांग की है। इसकी वजह से इस नए सीजन के शुगर प्रॉडक्शन में देरी हो सकती है। हालांकि इससे गन्ने के प्रति टन शुगर प्रॉडक्शन को बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में शुगर रिकवरी ज्यादा रहती है।

महाराष्ट्र के कोल्हापुर इलाके की शुगर मिलों ने फैसला लिया है कि जब तक गन्ने की कीमत को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक वे पेराई शुरू नहीं करेंगी। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने ऐलान किया है कि जब तक शुगर मिलें गन्ने के प्रति टन एफआरपी से 200 रुपये ज्यादा देने को राजी नहीं होती हैं, तब तक उनका संगठन मिलों को शुरू नहीं होने देगा।

स्टेट शुगर कमिश्नरेट के अधिकारियों के मुताबिक, पेराई के लाइसेंस के लिए जिन 194 शुगर मिलों ने आवेदन किए थे, उनमें से 55 मिलों को लाइसेंस मिल गए हैं और 32 मिलों ने शुगर प्रॉडक्शन शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया, '32 शुगर मिलों को पेराई के लाइसेंस दिए जाने के फैसले को रोक दिया गया है क्योंकि इन्होंने पिछले साल के एफआरपी का भुगतान नहीं किया है।' कोल्हापुर डिविजन की 5 मिलों ने कहा है कि

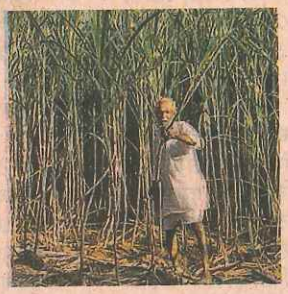

- किसान संगठनों ने गन्ने के एफआरपी से 200 रुपये ज्यादा की मांग की, मिलों ने कीमत पर स्थिति साफ होने के बाद कामकाज शुरू करने का फैसला किया

जब तक गन्ने की कीमत को लेकर विवाद हल नहीं हो जाता है, तब तक पेराई शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि विभाग को विश्वास है कि ज्यादातर मिलें 20 नवंबर तक चालू हो जाएंगी। दिवाली के बाद मजदूर भी फैक्ट्रियों में वापस आने लगेंगे। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि गन्ने की कीमत को लेकर जारी गतिरोध पर दिवाली के बाद ही कोई समाधान निकलेगा।

गन्ने की पेराई में इस देरी का शुगर प्रॉडक्शन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि नवंबर में शुगर रिकवरी काफी ज्यादा है। हालांकि, यह सूखा प्रभावित इस इलाके के किसानों की परेशानियों को बढ़ा सकता है क्योंकि उन्हें गन्ने की पेराई शुरू होने तक गन्ने के खेतों में सिंचाई करनी होगी।

Economic Times
1/11/2018